

सर्वमौल अथवा सार्वजनिक मानाधिकार

सच्चे लोकतन्त्र से नाकाम्य नहीं है कि शासन के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का भाग रहे। शासन, संसद में प्रविष्टियों का भेज कर ही यह सम्भव है। जिस पद्धति में प्रविष्टियों का निर्वाचन किया जाता है उस पद्धति को मन्दात कहते हैं। फिर मन्दात के अधिकार को मनाधिकार कहते हैं। जब राज्य के सभी नागरिकों को एक निश्चयन कर निर्धारित करके मनाधिकार प्रदान किया जाता है तो वह 'सर्वमौल अथवा सार्वजनिक व कर्षक मनाधिकार' कहलाता है। जो व्यक्ति इन अधिकार का उपयोग करने योग्य है उनका सामूहिक रूप में निर्वाचक कहलाते हैं।

प्रधानतः शासन प्रणाली में मन्दात का अधिकार सभी नागरिक-स्त्रियों एवं पुरुषों को मिलना चाहिए किन्तु कहीं-कहीं पर मन्दात का अधिकार सभी नागरिक-केवल-कर्षक पुरुषों को ही मिलता है। ऐसी स्थिति उस मनाधिकार को पुरुष मनाधिकार कहते हैं और स्त्रियों को मनाधिकार मिल जाये तो उसको स्त्री मनाधिकार का नाम से पुकारते हैं।

विद्वानों के यह मत प्रकृत किया है कि केवल आ लोगों को ही मनाधिकार प्रदान किया जाये जो संप्रदाय हैं और परिपक्व आयुवाले हैं। इस विचार से अमेरिका देशों में मनाधिकार का प्रयोग करने वाले सभी पुरुषों की निम्न-निम्न आयु निर्धारित की गई है। भारत इंग्लैंड तथा अमेरिका में 21 वर्ष, रूस में 18 वर्ष, जर्मनी में 22 वर्ष, बेल्जियम में 25 वर्ष, जापान में वयस्क मनाधिकार का प्रयोग करने वाले की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत में यह आयु 18 वर्ष ही रखा है।